RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2016-2018 IPT indianplasttimes@gmail.com
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

INDORE 20 SEPTEMBER TO 26 SEPTEMBER 2017 प्रति बुधवार वर्ष 03 अंक 04 पृष्ठ 8 कीमत 5 रु.

Inside News

प्राइवेट कंपनियों को मिल सकता है ONGC की फील्ड्स का कंट्रोल
Page 2

अपनी क्रिप्टोकरंसी 'लक्ष्मी' लॉन्च करेगा रिजर्व बैंक
Page 5

महिंद्रा लाई देश का पहला ड्राइवरलेस ट्रैक्टर
Page 7

editoria!

ब्लैक मनी के मुखौटे

दो लाख से ज्यादा शेल कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करके केंद्र सरकार ने काले धन के खिलाफ एक बेहद जरूरी कदम उठाया है। अच्छा होता कि इन कंपनियों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई की आंच इन्हें खोलने वालों तक भी पहुंचती, लेकिन अभी सरकार का जोर शेल कंपनियों को बंद करने और दिखावे के तौर पर इसके प्रबंधन से जुड़े लोगों पर नकेल कसने तक ही सीमित है। सरकारी निर्देश में कहा गया है कि जिन कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द हो चुका है, उनके निदेशक या अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता कंपनी के बैंक खातों से पैसा निकालने की कोशिश करेंगे, तो उन्हें 10 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा जिन शेल कंपनियों के निदेशकों ने तीन या अधिक वर्ष के लिए अपने रिटर्न दाखिल नहीं किए हैं, वे किसी अन्य कंपनी में भी ऐसा कोई पद नहीं ले सकेंगे। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने जिन 2 लाख 9 हजार से ज्यादा कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया है, उन्होंने लंबे समय से कोई कारोबारी गतिविधि नहीं की है। शेल कंपनियां सिर्फ कागज पर होती हैं, वे कोई आधिकारिक कारोबार नहीं करतीं। इनका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जाता है। सामान्य कंपनियों की तरह इनमें भी डायरेक्टर्स होते हैं। मामूली पगार वाले लोग दस-दस कंपनियों के बोर्ड में शामिल होते हैं, लेकिन इनके मालिक का नाम गुप्त रखा जाता है। शेल कंपनियों द्वारा निर्यात का फर्जी बिल बनाकर विदेशों से भारत में पैसे लाए जाते हैं। ऐसी कंपनियां बनाने वालों में कई राजनेता और बड़े कारोबारी भी शामिल हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कालेधन के खिलाफ अभियान तब तक पूरा नहीं होगा, जब तक इन चोर दरवाजों को पूरी तरह बंद न कर दिया जाए। दिक्कत यह है कि हमारे देश में आज भी ज्यादातर कारोबारी शत-प्रतिशत पारदर्शिता नहीं बरतते। प्रायः सभी कंपनियां दो तरह के खाते रखती हैं। एक अपने लिए, एक दिखाने के लिए। शेल कंपनी बनाकर टैक्स बचाना या कारोबार में लाभ कमाना बिजनेस का अनिवार्य अंग बन चुका है। चार्टर्ड एकाउंटेंट जैसे सम्मानित पेशे के लोग अपने हुनर का इस्तेमाल कारोबारियों को इस तरह के चोर दरवाजे सुझाने में करते हैं। शेल कंपनियों का मुद्दा पहले भी उठा है लेकिन इस मामले में कार्रवाइयां अंजाम तक नहीं पहुंच पाई हैं। आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय पहले भी इनके खिलाफ सक्रिय हुए, लेकिन उनके हाथ शेल कंपनियों के वास्तविक संचालकों तक पहुंचने से पहले ही रुक गए। वैसे शेल कंपनियों की परिभाषा को लेकर भी विवाद है। सरकार को इस मामले में भ्रम दूर करना चाहिए। वरना होगा वही, जो अब तक होता आया है। यानी मुखौटे पकड़ में आ जाएंगे, लेकिन इनके बल पर करोड़ों झटकने वाले मुख चैन से मुस्कुराते रहेंगे।

शेल कंपनियों पर सरकार ने बढ़ाई सख्ती

उजागर किये 55 हजार से ज्यादा डायरेक्टर्स के नाम

नई दिल्ली। एजेंसी

केंद्र सरकार ने मुखौटा कंपनियों और उनके संचालकों पर सख्ती बढ़ा दी है। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार ने ऐसी कंपनियों के 55 हजार से ज्यादा डायरेक्टरों के नाम सार्वजनिक कर दिए हैं। यह कदम इसलिए उठाया गया, ताकि इन लोगों को फिर किसी कंपनी में इसी तरह की भूमिका नहीं मिल सके।

सरकार ने ऐसी मुखौटा कंपनियों को चिह्नित किया है, जिन्होंने कोई कारोबारी गतिविधि नहीं की है, या जिनका लगातार तीन साल से वार्षिक रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं जमा कराया गया है। इन कंपनियों से जुड़े 1.06 लाख से ज्यादा डायरेक्टरों की पहचान भी की गई है। निकट भविष्य में बाकी निदेशकों के नाम भी उजागर किए जा सकते हैं। विभिन्न कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के पास पंजीकृत दो लाख से ज्यादा ऐसी कंपनियों का पंजीकरण रद किया जा चुका है। आरओसी द्वारा जारी की गई जनसूचनाओं के अनुसार अब तक चेन्नई की 24 हजार से ज्यादा ऐसी कंपनियों से जुड़े लोगों का नाम सार्वजनिक किया गया है।

इसी प्रकार अहमदाबाद और एर्नाकुलम में 12-12 हजार से ज्यादा कंपनियों से जुड़े निदेशकों के नाम उजागर किए गए हैं। इनके अतिरिक्त कटक, गोवा और शिलांग के आरओसी की ओर से भी डायरेक्टरों की सूची सार्वजनिक की गई है। दिल्ली, मुंबई और चंडीगढ़ के आरओसी ने अब तक सूची प्रकाशित नहीं की है।

माना जा रहा है कि इनमें से कई नाम बड़े राजनीतिक और कॉरपोरेट घरानों से जुड़े हो सकते हैं। हालांकि अभी इस बारे में इसलिए निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सूची में केवल डायरेक्टरों का नाम, उनका डीआइएन और कागजात में दर्ज पता दिया गया है। इसके अलावा उनकी कोई विस्तृत जानकारी नहीं है।

इसी महीने सरकार ने कहा था कि मुखौटा कंपनियों से जुड़े होने के कारण 1.06 लाख डायरेक्टर अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। मुखौटा कंपनियों पर कार्रवाई करते हुए कॉरपोरेट मामलों का मंत्रलय लंबे समय से कारोबार नहीं कर रही 2.09 लाख कंपनियों का पंजीकरण रद करने की प्रक्रिया में है। बैंकों को भी निर्देश दिया गया है कि इन कंपनियों के खातों में लेनदेन प्रतिबंधित कर दें।

मुखौटा कंपनियों पर कार्रवाई कंपनी कानून की धारा 248 के तहत हो रही है। इसके अनुसार कोई आरओसी रजिस्ट्रेशन के सालभर के भीतर व्यवसाय शुरू नहीं करने वाली या लगातार दो वित्त वर्ष तक कोई कारोबार नहीं करने वाली या तीन साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा नहीं कराने वाली कंपनियों का पंजीकरण रद कर सकता है।

लोकलुभावन तेवर और नए कलेवर में आएगा आम बजट - 2018

नई दिल्ली। एजेंसी

केंद्र सरकार ने आम बजट 2018-19 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। यह बजट 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का अंतिम पूर्ण होगा। इसलिए आगामी आम बजट न सिर्फ लोकलुभावन होगा, बल्कि यह बिल्कुल नए कलेवर में आएगा। वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग ने 13 सितंबर को बजट सर्कुलर जारी कर दिया है। इसी के साथ अगले वित्त वर्ष 2018-19 के आम बजट की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी विभाग के अधीन बजट डिवीजन आता है। यह डिवीजन ही देश का आम बजट तैयार करता है। विभाग ने सभी मंत्रालयों को नौ अक्टूबर से बजट-पूर्व बैठकों के लिए तैयार रहने को भी कहा है। मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक आगामी बजट में लोकलुभावन घोषणाओं पर जोर रहेगा। जीएसटी लागू होने के बाद सरकार के पास परोक्ष करों के मोर्चे पर बदलाव की ज्यादा गुंजाइश नहीं होगी। इसलिए माना जा रहा है कि इसमें प्रत्यक्ष करों खासकर आयकर और कॉरपोरेट टैक्स की दरें कम की जा सकती हैं। अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए सार्वजनिक आवंटन में भी वृद्धि के आसार हैं। खास बात यह है कि जीएसटी लागू होने के बाद केंद्र सरकार का यह पहला आम बजट होगा। इसलिए इसका कलेवर भी बदला-बदला नजर आएगा। वित्त मंत्री के बजट भाषण में भाग दो टैक्स से संबंधित होता है। सूत्रों का कहना है कि सरकार अब परोक्ष करों के मोर्चे पर पेट्रोलियम उत्पादों पर करों की दर में फेरबदल के अलावा बस बेसिक कस्टम ड्यूटी की दरों में कमी या बढ़ोतरी कर सकती है। जीएसटी लागू होने से केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर सहित केंद्र सरकार के कई परोक्ष कर और सेस खत्म होने के चलते बदलाव की अधिक गुंजाइश नहीं होगी। ऐसे में परोक्ष करों में बदलाव नहीं होने से वित्त मंत्री के बजट भाषण का भाग दो अपेक्षाकृत छोटा रहने की उम्मीद है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के आम बजट में भी कई बदलाव किए थे। साथ ही आम बजट पेश करने की तारीख भी फरवरी के अंतिम दिन से बदलकर पहले दिन कर दी थी।

गूगल का भुगतान एप 'तेज' पेश

मुंबई। एजेंसी

प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनी कंपनी गूगल ने भारतीय बाजार के लिए विशेष रूप से तैयार भुगतान एप 'तेज' पेश किया। कंपनी का कहना है कि इसके जरिए वह भारत में डिजिटल भुगतान को सरल व सुरक्षित बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। कंपनी का यह एप केंद्र सरकार के यूनीफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) पर आधारित है जो एंड्रॉयड व आईओएस चालित स्मार्टफोनों पर काम करेगा। कंपनी इस एप के जरिए लेनदेन के लिए कोई शुल्क नहीं लेगी और उपभोक्ता इसके जरिए अपने बैंक खातों से सीधे भुगतान कर सकेंगे और पैसा हासिल कर सकेंगे। गूगल के उपाध्यक्ष सीजर सेनगुप्ता ने कहा, यह उत्पाद भारत के लिए बनाया गया है। अनेक क्षेत्र हैं जिनमें भारत पश्चिमी देशों से आगे निकल जाएगा और ऐसा एक क्षेत्र भुगतान व वाणिज्य है'

प्राइवेट कंपनियों को मिल सकता है ONGC की फील्ड्स का कंट्रोल

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

देश की सबसे बड़ी ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ONGC) में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस सरकारी कंपनी की कुछ ऑयल एंड गैस फील्ड्स का कंट्रोल प्राइवेट कंपनियों को दिया जा सकता है। इसके अलावा कंपनी के रेवेन्यू में एक बड़ी हिस्सेदारी रिफाइनिंग और फ्यूल सेल्स की हो सकती है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री एक पॉलिसी को अंतिम रूप दे रही है जिसके तहत ONGC की कुछ प्रॉडक्शन करने वाली फील्ड्स का कंट्रोल प्राइवेट कंपनियों को देने की पेशकश की जाएगी। ये फील्ड्स ONGC को बिना ऑक्शन के दी गई थी। इन फील्ड्स से अधिक प्रॉडक्शन का वादा करने वाली कंपनियों को इनमें मेजॉरिटी स्टेक मिलेगा, जबकि ONGC के पास माइनॉरिटी स्टेक रहेगा। इन फील्ड्स को नॉमिनेशन फील्ड्स कहा जाता है। ONGC के क्रूड के

प्रॉडक्शन में नॉमिनेशन फील्ड्स की हिस्सेदारी लगभग 85 पर्सेंट की है। इन फील्ड्स की निगरानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स (DGH) कर रहा है। मई में एक ऑर्डर जारी कर इन फील्ड्स के लिए सुपरवाइजरी पैनल बनाया गया था। इस पैनल में तीन सदस्य DGH और दो ONGC से हैं। सरकार ने पिछले वर्ष ONGC की 63 छोटी फील्ड्स की नीलामी की थी। इन फील्ड्स की डिस्कवरी के बाद से कंपनी ने इन्हें डिवेलप नहीं किया था। अब सरकार की योजना इस वर्ष के अंत में होने वाली अगली नीलामी में ऐसी 20 और फील्ड्स को प्राइवेट कंपनियों को देने की है। उउप की ओर से पिछले महीने जारी की गई एक ड्राफ्ट पॉलिसी में उन छह फील्ड्स से ONGC के बाहर निकलने का प्रपोजल दिया गया था जिनमें कंपनी को पूरा सेस और रॉयल्टी चुकाने में फायदा नजर नहीं आ रहा था। इसमें यह भी प्रपोजल दिया गया था कि अगर प्राइवेट कंपनियां सरकारी रूल्स को मानने पर सहमत होती हैं तो उन्हें फील्ड्स का कंट्रोल दिया जा सकता है। हालांकि, ONGC के अधिकारियों ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा कि ONGC की फील्ड्स प्राइवेट कंपनियों को देने को लेकर सरकार जल्दबाजी कर रही है। लेकिन पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अधिकारियों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से स्थिर हो चुके देश के ऑयल और गैस प्रॉडक्शन को बढ़ाने के लिए इन उपायों की जरूरत है। एक अधिकारी ने कहा, 'यह समझना चाहिए कि ये ऑयल एंड गैस फील्ड्स राष्ट्रीय संसाधन हैं और अगर ONGC इन्हें डिवेलप नहीं कर पा रही है तो प्राइवेट कंपनियों को आगे आना होगा।'

सही दिशा में करें इनवेस्टमेंट

अपस्ट्रीम ऑयल सेक्टर में कॉस्ट को संतुलित करना और सही दिशा में इनवेस्टमेंट करना जरूरी है। ड्रिलिंग के लिए छोटी ऑयल फील्ड्स से बाहर निकलना और अपना खर्च कम करना बेहतर होगा। हालांकि, कंपनी को अपना मार्जिन बढ़ाने के लिए बेहतर संभावनाओं वाली फील्ड्स पर ध्यान देना होगा। इसे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इनवेस्टमेंट बढ़ाने की भी जरूरत है।

भारत ने अब चीन से आने वाले टायरों पर लगाई एंटी-डंपिंग ड्यूटी

नई दिल्ली। एजेंसी

घरेलू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को चीन से होने वाले सस्ते आयात से बचाने के लिए सरकार ने एक और उत्पाद पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। वित्त मंत्रालय ने चीनी रेडियन टायरों पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाई है। ये टायर बस, लॉरी और ट्रकों में इस्तेमाल किए जाते हैं। यह एंटी-डंपिंग ड्यूटी 5 साल के लिए लगाई गई है। हालांकि सरकार चाहे तो वह इसे पहले भी खत्म कर सकती है। संबंधित अथॉरिटी की तरफ से सुझाव मिलने के बाद वित्त मंत्रालय ने यह कदम उठाया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने 245.35 डॉलर प्रति टन से 452.33 डॉलर प्रति टन एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाई है। ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स ने अपोलो टायर्स, जेके टायर इंडस्ट्रीज और सीएट लिमिटेड की तरफ से याचिका दायर की थी। इसके बाद ही यह फैसला लिया गया है। इससे पहले अगस्त में सरकार ने चीन से आने वाले केमिकल कंपाउंड पीटीएफई और नॉन-स्टिक कोटिंग पर लगाई गई एंटी-डंपिंग ड्यूटी को भी 5 साल के लिए बढ़ा दिया था। यह कदम भी घरेलू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के हित की खातिर लिया गया था।

कोल इंडिया ने पावर प्लांट्स के लिए कोटा लिमिट हटाई

कोलकाता। एजेंसी

पावर प्लांट्स में कोयले की सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी जेनरेशन को बढ़ाने के लिए कोल इंडिया ने पावर प्लांट्स को उनके तय कोटा से अधिक कोयला देने की पेशकश की है। हालांकि, यह पेशकश ऐसे पावर प्लांट्स के लिए है, जो कोल इंडिया के पिटहेड से 60 किलोमीटर के दायरे में हैं और कोयले के ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रक का इस्तेमाल करते हैं।

कोल इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'हमने 20 माइंस की सूची दी है, जिनसे कंज्यूमर्स जितना चाहें कोल ले सकते हैं। पावर कंपनियों के अपने प्लांट तक कोयला ले जाने के लिए ट्रकों का इस्तेमाल करने से रेलवे की लंबी दूरी पर मौजूद प्लांट्स तक कोल पहुंचाने की क्षमता बढ़ने की उम्मीद है।'

60 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले प्लांट्स के लिए कोल इंडिया ने जितना अधिक संभव हो कोल भेजने का फैसला किया है जिससे इन प्लांट्स के पास पर्याप्त स्टॉक मौजूद रहेगा। कोल इंडिया ने पावर कंपनियों से कोल का पर्याप्त मात्रा में स्टॉक रखने के लिए भी कहा है। देश में बिजली बनाने के लिए कोल की डिमांड बढ़ी है और कोल इंडिया इसका इस्तेमाल अपने पिटहेड में मौजूद लगभग 3.3 करोड़ टन के स्टॉक को निकालने के लिए करना चाहती है। आने वाले समय में भी डिमांड बढ़ने की उम्मीद के कारण कंपनी ने अपना प्रॉडक्शन तेजी से बढ़ाने की योजना बनाई है। कंपनी के अधिकारी ने बताया, 'कोल प्रॉडक्शन बढ़ाना समस्या नहीं है, लेकिन मुश्किल माइन पर मौजूद कोल को थर्मल पावर प्लांट्स तक पहुंचाने की है।'

सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के अनुसार पिछले महीने हाइडल, न्यूक्लियर और अन्य सोर्सेज से पावर सप्लाई में क्रमशः 12 पर्सेंट, 36 पर्सेंट और 7 पर्सेंट की कमी आई। इसके नतीजे में थर्मल पावर प्लांट्स से पावर की डिमांड में काफी बढ़ोतरी हुई है।

अगस्त में कोल सप्लाई 20 पर्सेंट बढ़ने के कारण थर्मल पावर प्लांट्स पिछले वर्ष के इसी महीने के मुकाबले 17 पर्सेंट अधिक इलेक्ट्रिसिटी जेनरेट करने में कामयाब रहे। अधिकारी ने कहा, 'थर्मल पावर प्लांट्स को कोल की सप्लाई बढ़ाने के लिए हम अपने रिसोर्सेज को जुटा रहे हैं। कोल इंडिया और रेलवे पावर प्लांट्स को अधिक कोल भेजने के लिए मिलकर कोशिशें कर रहे हैं।'

गडकरी ने परिवहन क्षेत्र में सुधारों पर दिया बल

नयी दिल्ली। एजेंसी

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सार्वजनिक परिवहन में सुधार का आवान करते हुए आज राज्यों के परिवहन मंत्रियों से कर और परमिट के मुद्दों पर सुझाव देने को कहा। मंत्रालय के एक अधिकारी ने यह सुझाव दिया।

परिवहन विकास परिषद टीडीसी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने क्षेत्र में सुधार पर जोर दिया। केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री की अध्यक्षता वाली टीडीसी शीर्ष निकाय है जो क्षेत्र से जुड़े मामलों में परामर्श देता है।राज्यों के मंत्रियों से इस दिशा में काम करने और कर एवं परमिट पर सुझाव देने का आग्रह करते हुए गडकरी ने कहा, लोग बदलाव को स्वीकार करने को लेकर इच्छुक है।

उन्होंने जांच चौकियों को हटाने की वकालत करते हुए राज्यों से डिजिटल भुगतान समाधान व्यवस्था अपनाने को कहा।अधिकारी के अनुसार मंत्री ने राज्यों से वड़ोदरा की तर्ज पर आधुनिक बस बंदरगाह बनाने का अनुरोध किया। उन्होंने बसों के लिये बेहतर मानदंड के अलावा डबल डेकर पर भी जोर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसी बसों को राज्यों के बीच चलाये जाने की जरूरत है। परिषद ने जीएसटी व्यवस्था के तहत राज्य सीमाओं पर सुचारू परिवहन व्यवस्था पर चर्चा की। जीएसटी परिषद ने देश भर में बेरोकटोक परिवहन व्यवस्था के लिये उपायों के बारे में सुझाव देने को लेकर कार्यबल गठित किया है।

पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय में अगस्त के दौरान 10.9 प्रतिशत वृद्धि

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

देश में पर्यटन के जरिये होने वाली विदेशी मुद्रा आय अगस्त 2017 के दौरान 13,922 करोड़ रुपये रही जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 10.9 प्रतिशत अधिक है। सरकारी सूत्रों के अनुसार अगस्त 2016 में पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय 12,553 करोड़ रुपये और अगस्त 2015 में 11,411 करोड़ रुपये रही थी।जनवरी-अगस्त 2017 के दौरान यह आय 16.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1,16,004 करोड़ रुपये हो गई, जबकि जनवरी-अगस्त 2016 में यह 13.9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 99,587 करोड़ रुपये दर्ज की गई थी। अमेरिकी डालर के लिहाज से अगस्त, 2017 के दौरान विदेशी मुद्रा प्राप्ति 2.176 अरब अमेरिकी डॉलर रही, जबकि यह अगस्त 2016 में यह 1.875 अरब अमेरिकी डॉलर और अगस्त 2015 में 1.752 अरब अमेरिकी डॉलर दर्ज की गई थी। अमेरिकी डॉलर के लिहाज से अगस्त 2016 के मुकाबले अगस्त 2017 में विदेशी मुद्रा प्राप्ति में 16.1 प्रतिशत वृद्धि रही, जबकि अगस्त अगस्त 2016 में यह वृद्धि 7.0 प्रतिशत रही थी। जनवरी से अगस्त 2017 के दौरान अमेरिकी डालर में यह प्राप्ति 19.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 17.731 अरब अमेरिकी डॉलर हो गई, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 7.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 14.818 अरब अमेरिकी डॉलर दर्ज की गई थी। पर्यटन मंत्रालय रुपये एवं डॉलर दोनों ही लिहाज से भारत में हर महीने पर्यटन के जरिए विदेशी मुद्रा आमदनी का आकलन करता है।

छोटे कारोबारियों को तिमाही आधार पर जीएसटी रिटर्न भरने की सुविधा मिले

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

मध्यप्रदेश के वि मंत्री जयंत मलैया का कहना है कि 1.5 करोड़ रुपये तक के सालाना कारोबार वाली छोटी इकाइयों से हर महीने के बजाय प्रत्येक तीन माह में माल और सेवा कर जीएसटी का रिटर्न दाखिल कराया जाना चाहिये। मलैया ने माल और सेवा कर नेटवर्क जीएसटीएन का भार कम करने के लिये जीएसटी परिषद को यह सुझाव दिया है।

मलैया ने एक बैठक में शामिल होने के बाद संवाददाताओं से कहा, जीएसटी के दायरे में आने वाले 85 प्रतिशत कारोबारी ऐसे हैं जिनका सालाना कारोबार 1.5 करोड़ रुपये तक का है। इन कारोबारियों की बड़ी तादाद के कारण फिलहाल जीएसटीएन पर ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करते वक्त काफी भार पड़ रहा है।

उन्होंने कहा, इन हालात के मद्देनजर मेरा सुझाव है कि 1.5 करोड़ रुपये तक के सालाना कारोबार वाली इकाइयों के लिये प्रति माह के बजाय हर तीन महीने में जीएसटी रिटर्न भरने का प्रावधान तय कर दिया जाये, ताकि जीएसटीएन का बोझा घटाया जा सके।

मलैया ने बताया कि वह यह सुझाव वि मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई वाली जीएसटी परिषद की एक बैठक में भी रख चुके हैं। इसके साथ ही, उम्मीद जतायी कि जीएसटी परिषद की 24 अक्तूबर को दिल्ली में होने वाली अगली बैठक में उनके सुझाव पर चर्चा होगी और कोई रास्ता निकलेगा।

उन्होंने यह भी बताया कि मध्यप्रदेश में वाणिज्यिक कर विभाग की तर्ज पर आबकारी विभाग में अलग-अलग सर्किल बनाकर अधिकारियों की नियुक्ति की नयी व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है।

निर्यातकों की जीएसटी रिफंड प्रक्रिया तेज करने की मांग

नई दिल्ली। एजेंसी

निर्यातकों ने केंद्र सरकार से जीएसटी रिफंड प्रक्रिया को तेज करने की मांग की। क्योंकि उन्हें डर है कि इस मद में 65000 करोड़ रुपये की बड़ी राशि अटक सकती है। राजस्व सचिव हसमुख अधिया की अध्यक्षता वाली निर्यातकों की समिति ने आठ निर्यात संवर्धन संगठनों से मुलाकात की। ताकि जीएसटी के कार्यन्वयन के बाद उनकी चिंताओं को समझा जा सके। बैठक के बाद फियो के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा, 'अगर रिफंड मिलना तत्काल शुरू नहीं होता है तो अक्टूबर के आखिर तक 65000 करोड़ रुपये अटक सकते हैं।' इससे निर्यातकों की नकदी स्थिति और खराब होगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार इस बारे में जल्द फैसला करेगी ताकि निर्यातकों को अन्य क्षेत्रों के समान अवसर मिल सके। बैठक के दौरान निर्यातकों ने जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3बी डेटा के आधार पर रिफंड की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने पर जोर दिया। अभियांत्रिकी निर्यात संवर्धन परिषद के बोर्ड सदस्य पीके शाह ने कहा कि आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए यह महत्वपूर्ण है कि अधिकारी उठाव के बाद ही कम से कम 90 प्रतिशत रिफंड जारी कर दें। चमड़ा निर्यात परिषद के वायस चेयरमैन पी अहमद ने कहा कि जीएसटी के चलते निर्यातकों के समक्ष चुनौतियां हैं और उन्हें करों के तुरंत रिफंड की जरूरत है।

GST और बैंकरप्सी कोड से इंडिया में बढ़ेगा FDI: मूडीज

नई दिल्ली। एजेंसी

गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी और बैंकरप्सी कोड जैसे रिफॉर्म्स के चलते भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अच्छा-खासा बढ़ सकता है। इंटरनैशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है। मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, 'कारोबार के तौर-तरीकों की जटिलता घटाने और उसकी लागत में कमी लाने वाले जीएसटी और सरल बैंकरप्सी कोड जैसे रिफॉर्म्स होने के चलते एफडीआई में बढ़ोतरी हो सकती है।' सोमवार को जारी रिपोर्ट इस विषय पर आधारित है कि कैसे ग्लोबल डिमांड में मजबूती से एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों में बुनियादी सुधारों का ज्यादा असर हो सकता है।

मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सरकार ने कई सेक्टरों में ऑथराइज्ड एफडीआई की ऊपरी सीमा बढ़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, 'भारत में एफडीआई लिमिट पहले से ही बहुत बढ़ी हुई है। यह अलग बात है कि उनका आधार छोटा है।' डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऐंड प्रमोशन के मुताबिक, पिछले साल देश में एफडीआई 18 पर्सेंट बढ़कर $46 अरब हो गया था। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने इंश्योरेंस, डिफेंस, सिविल एविएशन सहित बहुत से सेक्टर में एफडीआई फ्रेमवर्क को उदार बनाया है। इसके साथ ही देश में कारोबार करना आसान बनाने के लिए कई तरह के कदम उठाए हैं।

इंटरनैशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा है कि इंडिया और इंडोनेशिया में कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के साथ ही बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदमों के सकारात्मक असर की झलक मजबूत मैक्रोइकनॉमिक माहौल में ज्यादा अच्छी दिखेगी। मूडीज ने इंडिया की Baa3 पॉजिटिव सॉवरेन रेटिंग बरकरार रखी है।

मूडीज ने कहा है कि इंडिया और इंडोनेशिया, दोनों देशों की सरकारों ने अपने यहां कारोबारी हालात बेहतर बनाने, खासतौर पर एफडीआई आकर्षित करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई सुधार कार्यक्रम लागू किए हैं। उसके मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार की मजबूती से विदेशी निवेशकों के बीच दोनों देशों के आकर्षण पर आर्थिक सुधारों का सकारात्मक असर बढ़ सकता है।

मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज ने कहा है कि पिछले साल के अंत से अब तक ग्लोबल डिमांड में आ रही मजबूती से एशिया प्रशांत की ट्रेड आधारित अर्थव्यवस्थाओं की ग्रोथ तो बढ़ी है लेकिन उनकी तेज एक्सपोर्ट ग्रोथ टिकाऊ प्रॉडक्शन ग्रोथ में बढ़ावा देने में कामयाब नहीं हो पाई है।

मार्केट के अच्छे दिन जारी

निफ्टी 10161, सेंसेक्स 32467 स्तर पर खुला

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

घरेलू मार्केट के लिए यह कारोबारी हफ्ता काफी अच्छा साबित होता नजर आ रहा है। बुधवार को तीसरे दिन लगातार बाजार ने तेजी के साथ शुरुआत की है। बुधवार को निफ्टी जहां 10161 के स्तर पर खुला। वहीं, सेंसेक्स 32467 स्तर पर बना हुआ है। सेंसेक्स 65 अंक मजबूत हुआ। वहीं, निफ्टी 13 अंक की बढ़त के साथ खुला। मंगलवार को शुरू हुई यूएस फेडरल रिजर्व की बैठक के बीच घरेलू मार्केट में सकारात्मक रुझान देखने को मिल रहा है। बुधवार को शुरुआती कारोबार में बैंकिंग शेयर्स की मजबूत शुरुआत रही। इनमें बढ़त देखने को मिल रही है। बुधवार को रुपये की मजबत शुरुआत हुई। डॉलर के मुकाबले रुपया 8 पैसे बढ़कर 64.25 के स्तर पर खुला। मंगलवार को रुपया डॉलर के मुकाबले 19 पैसे की कमजोरी के साथ 1 डॉलर के मुकाबले 64.33 के स्तर पर बंद हुआ था।

30 सितंबर के बाद बेकार हो जाएंगे इन 6 बैंकों के चेक

जल्द उठाएं ये कदम

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के अनुषंगी बैंकों के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। इन बैंकों के चेक आगामी 30 सितंबर के बाद से अमान्य हो जाएंगे। इसलिए यदि आप भी इन बैंकों के खाताधारक हैं, तो चेक बुक बदलने के लिए अभी से आवेदन कर दें। एसबीआई ने कहा है कि उसके पूर्व सहयोगी बैंक और भारतीय महिला बैंक के सभी ग्राहकों से अनुरोध किया जाता है कि खाताधारक नई चेकों के लिए अभी से आवेदन कर दें। पुरानी चेक बुक और आईएफएससी कोड 30 सितंबर के बाद अमान्य हो जाएंगे। नई चेक बुक के लिए इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम या फिर शाखा में जाकर आवेदन करना होगा। एक अप्रैल 2017 से एसबीआई के अनुषंगी बैंकों स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर (एसबीबीजे), स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (एसबीएच), स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (एसबीएम), स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (एसबीपी), स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (एसबीटी) और भारतीय महिला बैंक (बीएमबी) का एसबीआई में विलय हो चुका है। देश के सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक ने इन बैंकों के ग्राहकों से कहा है कि वे 11 दिनों के पहले इन पांच बैंकों से संबंधित चेकबुक का इस्तेमाल बंद कर दें। साथ ही नई चेकबुक पाने के लिए अभी से आवेदन करना शुरू कर दें, ताकि 30 सितंबर के बाद उन्हें लेन-देन करने में कोई परेशानी नहीं उठानी पड़े।

नौकरी छोड़ने पर आपको मिलेगी कितनी ग्रेच्युटी

ऐसे होता है तय

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

केंद्र सरकार ने निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह अब निजी और पीएसयू के कर्मचारियों के लिए भी 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी राशि कर मुक्त कर दी है। अभी तक यह सीमा 10 लाख रुपए थी। इसके लिए सरकार जल्द संसद में विधेयक पेश करेगी। सरकार के इस फैसले से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले करीब पांच करोड़ लोगों को फायदा होगा। केंद्रीय कर्मचारियों के गठित सातवें वेतन आयोग ने ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने की सिफारिश की थी। इसके आधार पर केंद्र और कई राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए इसे लागू कर चुकी है।

इन संस्थानों पर लागू होता है नियम

सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि ग्रेच्युटी भुगतान कानून 1972 उन संस्थानों पर लागू होता है, जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं। इसका मुख्य मकसद कर्मचारियों को सेवानिवृति के बाद आर्थिक सुरक्षा देना है। कई बार कर्मचारी सेवानिवृति की निर्धारित उम्र सीमा के पहले भी विकलांगता या अन्य किसी वजह से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ऐसे में ग्रेच्युटी आय की मुख्य जरिया बन सकती है।

ऐसे होती है ग्रेच्युटी की कैल्कुलेशन

कानून के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी किसी संगठन में कम से कम पांच सालों तक लगातार काम करता है, तो कंपनी को उसे ग्रेच्युटी देनी होती है। हर साल की सेवा के लिए संगठन को अंतिम वेतन के 15 दिनों के बराबर राशि का भुगतान करना होता है।

वेतन का मतलब वेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता और कमीशन इसमें शामिल होता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति 6 महीने से अधिक समय तक काम करता है, तो इसे ग्रेच्युटी गणना के लिए एक पूर्ण वर्ष गिना जाता है। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति 7 साल और 6 महीने की निरंतर सेवा पूर्ण करता है, तो ग्रेच्युटी का भुगतान 8 वर्षों के लिए किया जाएगा।

ग्रेच्युटी गणनाओं के लिए एक महीने का काम 26 दिनों के रूप में गिना जाता है। 15 दिन के वेतन की गणना के लिए मासिक वेतन में 15 का गुणा करके 26 से भाग दिया जाता है। इस संख्या को सेवा में वर्षों की संख्या से गुणा किया जाता है और जो राशि आती है, वह भत्ते के रूप में देय होती है।

यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाए

यदि कोई कर्मचारी पांच साल की सेवा करने से पहले ही मर जाता है, तो न्यूनतम 5 वर्ष का क्लॉज उस पर लागू नहीं होता है। अर्जित राशि को कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारी को कंपनी को भुगतान करना होता है। ये सभी भुगतान कर्मचारी के अंतिम कार्य दिवस के 30 दिनों के भीतर करने होते हैं। यदि भुगतान में 30 दिनों से अधिक की देरी हो, तो कानून कहता है कि नियोक्ता को उस राशि पर ब्याज का भुगतान करना होगा।

सेबी ने सुरक्षा चुनौतियों को लेकर उठाया कदम

एजेंसी की लेगी सेवा

नई दिल्ली। एजेंसी

बाजार नियामक सेबी की नेटवर्क और सुरक्षा परिचालन केंद्र के गठन के लिए बाहरी एजेंसियों (थर्ड पार्टी) की सेवा लेने की योजना है। इससे नियामक प्रभावी तरीके से रैंसमवेयर से उत्पन्न चुनौती समेत अन्य सुरक्षा संबंधी खतरों का प्रभावी तरीके से पता लगा सकेगा और उससे बचाव कर सकेगा। सेबी ने ये सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नोटिस जारी कर रूचि पत्र आमंत्रित किया है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब भारत समेत कई देशों में साइबर हमले तेज हुए हैं।

साइबर हमलों को लेकर सतर्क

हालांकि शेयर बाजारों में अब तक कोई बड़े हमले नहीं हुए हैं, लेकिन एक्सचेंज बार-बार सूचीबद्ध कंपनियों और विभिन्न मध्यस्थों को अपनी प्रणाली दुरूस्त करने को लेकर आगाह कर रही है और सभी प्रकार के साइबर हमलों को लेकर लगातार नजर रख रहे हैं। सेबी ने एक नोटिस में कहा कि संबंधित पक्ष अत्याधुनिक नेटवर्क और सुरक्षा परिचालन केंद्र स्थापित करेगी और नियामक की सुरक्षा समाधान को क्रियान्वित

और उसका उन्यन करेगा।

सूचीबद्ध कंपनियों में अलग चेयरमैन व प्रबंध निदेशक के पद

सेबी के एक समिति के सूचीबद्ध कंपनियों में चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (एमडी) पद अलग करने के फायदों पर जोर देने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां इस पर सबसे पहले अमल कर सकती हैं। सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में अंतिम निर्णय सेबी करेगा, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पहले ही चेयरमैन और प्रबंध निदेशक पद अलग कर चुके हैं। सार्वजनिक बैंकों ने सरकार और रिजर्व बैंक के निर्णय लेने के बाद ऐसा किया। सेबी ने अभी दोनों पदों को अलग करना अनिवार्य नहीं किया है। उसके नियम के अनुसार, सूचीबद्ध कंपनियां हितों के टकराव से बचने के लिए स्वेच्छा से ऐसा निर्णय ले सकती हैं। समिति के एक सदस्य ने बताया कि कंपनी संचालन पर बनी सेबी की समिति नियामक को इस संबंध में सुझाव देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

नियमों के पालन न करने पर खरीद पर रोक

सेबी ने सार्वजनिक निर्गम नियमों का पालन किए बिना बाजार से धन जुटाने पर कोलकाता की कंपनी अग्रगामी एग्रो फार्म्स लिमिटेड (एएएफएल) और उसके निदेशकों को प्रतिभूति बाजार का उपयोग करने से रोक दिया है। सेबी ने अपने दिनांक 18 सितंबर के आदेश में कहा कि यह फैसला तब तक लागू रहेगा जब तक इस पर कोई और आदेश नहीं आता। सेबी को कंपनी के खिलाफ विमोचनीय तरजीही शेयर और सुरक्षित विमोचनीय ऋणपत्र जारी कर पैसे जुटाने को लेकर शिकायतें मिली थी। इसके अलावा, 2010-11 में 668 लोगों और 2011-12 में 133 लोगों से ऋणपत्र के जरिए 1.92 करोड़ रुपये जुटाए थे।

नीति आयोग को मेंटर इंडिया अभियान के तहत मिलें 5,000 आवेदन

नयी दिल्ली। एजेंसी

नीति आयोग को अपने मेंटर इंडिया अभियान को लेकर अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। इसके तहत आयोग को 5,000 आवेदन मिले हैं। इस अभियान का मकसद अटल नवाचार मिशन के एक हिस्से के रूप में देश भर में स्थापित अटल टिंकरिंग लैब में छात्रों के मार्गदर्शन के काम में अग्रणी भूमिका निभाने वाले लोगो को शामिल करना है। अटल टिंकरिंग लैब ऐसे वर्क स्टेशन हैं, जहॉ छठी कक्षा से लेकर बारहवीं कक्षा के छात्र नवीन कौशल सीखेंगे और ऐसी अवधारणाएं विकसित करेंगे जिससे भारत की तस्वीर बदले। उद्योग मंडल एसोचैम के एक कार्यक्रम में अटल नवाचार मिशन एआईएम के मिशन निदेशक रामनाथन रमणन ने कहा कि इस अभियान को शानदार प्रतिक्रिया मिली है। कुल 5,000 आवेदन आये हैं। यह अभियान नीति आयोग चला रहा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचि जनजाति और महिला उद्यमियों के सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि इसकी संख्या और अधिक हो। हमारे पास कम-से-कम 10,000 से 15,000 अनुभवी संरक्षक-प्रशिक्षक मेंटर होने चाहिए क्योंकि देश बड़ा है, स्कूल काफी फैले हैं और हमें लोगों की मदद की जरूरत है। अभियान के तहत आवेदन को लेकर लिंक 30 सितंबर तक खुला है। रमणन ने जोर देकर कहा, हम पूरे देश में प्रत्येक पेशेवर संगठनों से संरक्षकों का एक नेटवर्क तैयार करने जा रहे हैं जो इसके समर्थन में सक्षम है....। उन्होंने कहा कि एआईएम की पहल के तहत सरकार भविष्य के नवोन्मेषों को तैयार करना चाहती है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवप्रवर्तन और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये एआईएम की शुरूआत की। इस कार्यक्रम के तहत देश भर में स्कूलों में टिंकरिंग लैब स्थापित किये जा रहे हैं। अब तक करीब 1,000 स्कूलों में टिंकरिंग लैब स्थापित किया जा चुके हैं। ये लैब छात्रों को थ्री डी प्रिंटरों, रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स औजारों, इंटरनेट और सेंसरों आदि जैसे अत्याधुनिक उपकरणों के बारे में जानकारी देंगे। सरकार की इस साल के अंत तक 2,000 टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना है। उल्लेखनीय है कि मेंटर इंडिया अभियान का लक्ष्य अटल टिंकरिंग लैब के प्रभाव को अधिकतम बनाना है। यह संभवतः वि भर में औपचारिक शिक्षा के सबसे बड़े प्रसार के अभियान की पहल है। इसकी अवधारणा मे अग्रणी हस्तियों को इस अभियान से जोड़ना है जो अटल टिंकरिंग लैबों मे छात्रों का मार्गदर्शन करेंगे।

कंपनियों, टैक्सपेयर्स को 15 नवंबर तक देनी होगी इनकम अनुमान की जानकारी

नई दिल्ली। एजेंसी

अपने एकाउंट्स की ऑडिटिंग करवाने वाली कंपनियों और टैक्सपेयर्स को फाइनेंशियल ईयर के छह महीनों के लिए इनकम के अनुमान और टैक्स देनदारी की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 15 नवंबर तक देनी होगी। इस कदम का मकसद रेवेन्यू के फ्लो पर करीबी नजर रखना है।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) की ओर से जारी एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में इनकम और चुकाए गए एडवांस टैक्स के विवरण देने के लिए फॉर्म 28AA भरने पर 29 सितंबर तक राय मांगी गई है। इसके अलावा कारोबारियों को पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में इनकम के भुगतान में किसी कमी के कारण भी बताने होंगे। इस जानकारी से टैक्स डिपार्टमेंट को लगभग वास्तविक समय में फर्म की इनकम के ट्रेंड का पता लगाने में मदद मिलेगी। जिन मामलों में कुल इनकम पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में 5 लाख रुपये तक या 10 पर्सेंट, जो भी अधिक है, घटी है, उनमें टैक्सपेयर्स को अप्रैल-दिसंबर की अवधि के लिए 31 जनवरी

तक इनकम और टैक्स देनदारी का इसी तरह का विवरण देना होगा। मौजूदा सिस्टम में, टैक्सपेयर्स को पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए देनदारी वाले इनकम टैक्स पर एडवांस टैक्स चार किस्तों में चुकाना होता है। इन किस्तों का भुगतान 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च तक किया जाता है। CBDT की योजना इनकम टैक्स रूल्स में रूल 39A को शामिल करने की है। इसके तहत अपने एकाउंट्स का ऑडिट कराने वाली कंपनियों और टैक्सपेयर्स के लिए इनकम और चुकाए गए टैक्स के विवरण देने वाले फॉर्म 28AA को जमा करना अनिवार्य हो जाएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस कदम का मकसद टैक्स कलेक्शन पर करीबी नजर रखना है। अशोक माहेश्वरी एंड एसोसिएट्स LLP के पार्टनर, अमित माहेश्वरी ने कहा, 'इसका उद्देश्य रेवेन्यू कलेक्शन पर कड़ी निगरानी रखने का हो सकता है।' उन्होंने कहा कि अभी तक टैक्स अधिकारी बड़े टैक्सपेयर्स पर एडवांस टैक्स चुकाने के लिए दबाव डालते थे। अब यह प्रक्रिया औपचारिक बनाई गई है।नांगिया एंड कंपनी की एसोसिएट डायरेक्टर, शालू केडिया ने बताया कि वर्तमान एडवांस टैक्स अनुमानित इनकम के आधार पर चुकाया जाता है और एडवांस टैक्स के भुगतान में किसी कमी पर रिटर्न दाखिल करने के समय टैक्स लगाया जाता है।

बेनामी संपत्ति के मामले में 450 लोगों को नोटिस

नई दिल्ली। एजेंसी

ब्लैक मनी के खिलाफ सरकार ने जो अभियान छेड़ा हुआ है, अब उसकी रेडार पर बेनामी सम्पत्ति रखने वाले आ गए हैं। सरकार ने 450 ऐसे लोगों की पहचान की है, जिनके पास मोटी राशि यानी करोड़ो रुपये की बेनामी सम्पत्ति हैं। इन बेनामी सम्पत्ति मालिकों को नोटिस भेज दिया गया है। अगर इन लोगों ने नोटिस का जवाब नहीं दिया तो इनके खिलाफ बेनामी सम्पत्ति ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। इनकी सम्पत्ति जब्त भी की जा सकती है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार वैसे पिछले 10 महीने में मुंबई दिल्ली समेत 14 राज्यों के करीब 650 बेनामी संपत्ति पर कार्रवाई की गई है। अब तक कितनी संपत्ति जब्त की गई है। पिछले 10 महीने में 2300 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति पर कार्रवाई की गई हैं।

बड़े बेनामी सम्पत्ति के मालिक

इनकम टैक्स विभाग के सूत्रों के अनुसार जिन 450 लोगों को बेनामी सम्पत्ति के मामले में नोटिस भेजा गया है, उनके पास करोड़ों रुपये की बेनामी सम्पत्ति होने का शक है। नोटिस भेजने के 15 दिनों के भीतर इनको जवाब देना होगा। अगर ये लोग जवाब नहीं देते तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी। अगर इन्होंने जवाब दिया तो यह देखा जाएगा कि इन सम्पत्तियों का ब्यौरा इन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न में दिया है कि नहीं। अगर दिया है तो वह कितना सही है। अगर जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो फिर इनसे पूछताछ की जाएगी।

सम्पत्ति जब्त की जाएगी

अगर जांच में यह साबित हो गया कि इनके पास बेनामी सम्पत्ति है तो नवंबर 2016 से लागू बेनामी संपत्ति ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत इनकी सम्पत्ति जब्त की जाएगी। इनके खिलाफ टैक्स चोरी और ब्लैक मनी खपाने का मामला भी बनेगा। अगर इनके खिलाफ वित्तीय आपराधिक या धन शोधन का मामला बना तो इनको सजा भी हो सकती है। इनकम टैक्स के सूत्रों का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो बेनामी सम्पत्ति के जांच में ईडी और अन्य जांच एजेंसियों की मदद भी ली जाएगी।

सरकार को शक

सरकार को शक है कि शेल कंपनियां बनाकर लोग बेनामी सम्पत्तियों की खरीददारी कर रहे हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ऐसे लोगों को साफ चेतावनी दी है कि उनकी संपत्तियां जब्त की जाएंगी। वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि शेल कंपनी के जरिए बेनामी सम्पत्ति खरीदने वाले या इस रूट से पैसा लाने वालों में न सिर्फ बिजनेसमैन, बल्कि राजनेता और बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग ने बेनामी संपत्तियों की पहचान शुरू कर दी है और जल्द ही इन पर कार्रवाई की जाएगी।

पेट्रोलियम उत्पादों पर समान कर की जरूरतः प्रधान

हैदराबाद। आईपीटी नेटवर्क

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए पेट्रोलियम पदार्थों को माल एवं सेवा कर जीएसटी के दायरे में लाने के लिए वित्त मंत्रालय से अपील की है। अपने कदम को सही ठहराते हुए प्रधान ने कहा कि पूरे देश में एकसमान कर व्यवस्था होनी चाहिए। प्रधान ने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाना पेट्रोलियम मंत्रालय का प्रस्ताव है। हमने राज्य सरकारों और वित्त मंत्रालय से पेट्रोलियम वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में लाने की अपील की है। उपभोक्ताओं के हितों को देखते हुए करों को युक्तिसंगत रखने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों पर दो तरह के कर लगते हैं, जिसमें एक केंद्रीय उत्पाद शुल्क और दूसरा वैट है। यही कारण है कि उद्योग के दृष्टिकोण से समान कर तंत्र की उम्मीद कर रहे हैं।

दैनिक आधार पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों की समीक्षा को सही ठहराते हुए प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जो भी शुल्क एकत्रित किया जाता है उसमें से राज्यों को 42 प्रतिशत हिस्सेदारी प्राप्त होती है। पेट्रोल और डीजल का घरेलू मूल्य अंतरराष्ट्रीय कीमतों से निर्धारित होता है। जो भी अंतरराष्ट्रीय कीमत होती है वहीं उपभोक्ताओं के पास जाती है। जब कीमतों में वृद्धि होती है तो हमें बढ़ोत्तरी करनी पड़ती है, उसी तरह जब गिरावट आती है हम दामों में कमी करते हैं। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा, केंद्रीय कर का 42 प्रतिशत हिस्सा राज्यों से आता है और राज्यों की अपनी स्वयं की कर प्रणाली है। राज्यों से आ रहे कर संग्रह का एक बड़ा हिस्सा उपयोग किया जाता है। उन्होंने कहा कि देश में विभिन्न कल्याणकारी परियोजनाओं को लागू करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। क्या आपको नहीं लगता कि हमें अच्छी सड़कों का निर्माण करना चाहिए, क्या आपको नहीं लगता कि हमें नागरिकों को साफ पेयजल देना चाहिए। भारत सरकार के खर्च को देखिए। पहले गरीबों की आवासीय योजना पर सरकार 70,000 प्रति इकाई खर्च करता थी और अब 1.5 लाख रुपये खर्च कर रही है। उन्होंने कहा, आपको क्या लगता है सरकार को ये पैसा कहां से मिलता है आप सोचते हैं कि हमने खजाने में पैसा रखा हुआ है। हम अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बुनियादी ढांचा निर्माण में पैसा खर्च कर रहे हैं।

बिटकॉइन के विकल्प के तौर पर अपनी क्रिप्टोकरंसी 'लक्ष्मी' लॉन्च करेगा रिजर्व बैंक

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले साल नोटबंदी कर दुनिया को चौंका दिया था, लेकिन करंसी के साथ उसका यह आखिरी प्रयोग नहीं था। भारतीय रिजर्व बैंक अब क्रिप्टोकरंसी की दिशा में कदम आगे बढ़ाने पर विचार कर रहा है। दुनिया की पहली क्रिप्टोकरंसी बिटकॉइन की लोकप्रियता के बाद भारतीय रिजर्व बैंक अपनी क्रिप्टोकरंसी लाने पर विचार कर रहा है। हालांकि अब तक वह इस गैर-व्यवस्थित कही जाने वाली करंसी को लेकर बहुत सहज नहीं था। आरबीआई ने भले ही लोगों को वर्चुअल करंसी के इस्तेमाल के प्रति चेताया हो, लेकिन एक घरेलू बिटकॉइन एक्सचेंज का कहना है कि हर दिन उसके 2,500 यूजर बढ़े हैं और डाउनलोड 5 लाख हो गए हैं।

2015 में लॉन्च हुई कंपनी का कहना है कि लगातार बढ़ते डाउनलोड्स से पता चलता है कि लोगों को बिटकॉइन पर भरोसा बढ़ा है और यह करंसी सबसे लोकप्रिय इमर्जिंग असेट्स क्लास के तौर पर उभरी है। आरबीआई में एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप भारतीय करंसी रुपये के डिजिटल विकल्प की संभावनाओं पर विचार कर रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक धन की देवी के नाम पर आरबीआई अपने बिटकॉइन का नाम 'लक्ष्मी' रख सकता है।

आरबीआई की क्रिप्टोकरंसी उसकी उस योजना का हिस्सा हो सकता है, जिसके तहत वह ब्लॉकचेन तैयार करने पर विचार कर रहा है। क्रिप्टोकरंसीज के लेनदेन का लेजर रेकॉर्ड रखने वाली

व्यवस्था को ब्लॉकचेन कहा जाता है। फ्रॉड और बैड लोन से निपटने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अन्य बैंकों और तकनीकी कंपनियों के साथ मिलकर इस पर काम कर रहा है। इस मामले में एसबीआई आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, स्काइलार्क, केपीएमजी और 10 कमर्शिल बैंकों के साथ काम कर रहा है।

जानें, क्या है क्रिप्टोकरंसी

क्रिप्टोकरंसी को ई-मुद्रा भी कह सकते हैं। यह आपके नोटों की तरह नहीं होती है, केवल कंप्यूटर पर ही दिखाई देती है और सीधे आपकी जेब में नहीं आती। इसलिए इसे डिजिटल या वर्चुअल करंसी कहा जाता है। इसलिये इसे डिजिटल करेंसी, वर्चुअल करेंसी (क्रिप्टोग्राफी) कहते हैं। इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी। इसके इस्तेमाल और भुगतान के लिये क्रिप्टोग्रफी का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इसे क्रिप्टोकरंसी कहा जाता है। बिटकॉइन को दुनिया की पहली क्रिप्टोकरंसी कहा जाता है। इसको जमा करना माइनिंग कहलाता है। क्रिप्टोकरंसी को दुनिया के किसी भी कोने में आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है और किसी भी प्रकार की करसी में कनवर्ट किया जा सकता है जैसे डॉलर, यूरो और रुपया आदि।

जानें, क्या होती है क्रिप्टोग्रफी

क्रिप्टोग्रफी एक प्रकार का कूट लेखन यानी एनकोडिंग है। इसमें भेजे गये संदेश या बिटकॉइन या जानकारी को सांकेतिक शब्दों में बदलना होता है, जिससे उसे भेजने वाला या रिसीव करने वाला ही पढ़ पाए।

TRAI के नए फैसले से मोबाइल कॉल हो सकती है सस्ती

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

देश में मोबाइल से कॉल करना सस्ता हो सकता है। दूरसंचार नियामक ट्राई के ताजा फैसले से यह संभव होगा। नियामक ने कॉल कनेक्ट करने के लिए एक टेलीकॉम ऑपरेटर द्वारा दूसरे को अदा किए जाने वाले कॉल टर्मिनेशन शुल्क को 14 पैसे से घटाकर छह पैसे प्रति मिनट कर दिया है। शुल्क की नई दर पहली अक्टूबर से लागू होगी। यही नहीं, जनवरी, 2020 से इस शुल्क को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) का यह फैसला टेलीकॉम कंपनियों की मांग से एकदम उलट है। भारती एयरटेल समेत विभिन्न टेलीकॉम कंपनियों ने कॉल टर्मिनेशन शुल्क को बढ़ाए जाने तथा इसकी न्यूनतम लाभप्रद दर तय करने की मांग की थी। हालांकि सबसे नई कंपनी रिलायंस जियो ने इसका विरोध करते हुए टर्मिनेशन चार्ज को पूरी तरह खत्म करने की पैरवी की थी। जियो का कहना था कि ऐसा करने से ग्राहकों को फायदा होगा। ट्राई ने इस निर्णय के बारे कहा कि तमाम हितधारकों से प्राप्त लिखित और मौखिक टिप्पणियों के आधार पर घरेलू मोबाइल टर्मिनेशन शुल्क की नई दरें तय की गई हैं। नए नियमों के अनुसार मोबाइल से मोबाइल के बीच कॉल पर टर्मिनेशन शुल्क की दर पहली अक्टूबर 2017 से 14 पैसे के बजाय छह पैसे प्रति मिनट होगी। अन्य सभी प्रकार की कॉल (जैसे कि वायरलाइन से वायरलाइन और वायरलाइन से मोबाइल) के लिए टर्मिनेशन शुल्क शून्य रहेगा। जबकि पहली जनवरी, 2020 से सभी प्रकार की घरेलू कॉल पर टर्मिनेशल शुल्क समाप्त हो जाएगा। फिलहाल लागू 14 पैसे प्रति मिनट का टर्मिनेशन चार्ज एक मार्च, 2015 को लागू हुआ था। इस शुल्क को इंटर कनेक्ट चार्ज (आइयूसी) भी कहा जाता है।

जनसंपर्क उद्योग 18 प्रतिशत की दर से बढ़कर 1,315 करोड़ रुपये का हुआ

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

जन संपर्क पीआर उद्योग वि‍ा वर्ष 2016-17 के दौरान 18 प्रतिशत की दर से वृद्धि हासिल कर 1,315 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। भारतीय जनसंपर्क सलाहकार संघ पीआरसीएआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, जनसंपर्क उद्योग में आगे भी तेज विकास की उम्मीद है और यह 2020 तक दो हजार करोड़ रुपये का हो जाने की उम्मीद है। वि‍ा वर्ष 2015-16 में यह 1,120 करोड़ रुपये का था। पीआरसीएआई के अध्यक्ष और एवियन मीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नितिन मंत्री ने कहा, संवाद के तरीके और माध्यम तेजी से बदल रहे हैं। आज के समय में पीआर कंपनियों के लिए सतत नवाचार और बदलते परिदृश्य को अपनाना अनिवार्य हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि क्षेत्र की वृद्धि को खुदरा, वाहन और एफएमसीजी क्षेत्र से समर्थन मिला है। बड़ी कंपनियों के एफएमसीजी और खुदरा राजस्व में 14 प्रतिशत की तेजी आयी है। हालांकि, सूचना एवं प्रसारण प्रौद्योगिकी क्षेत्र में गिरावट आयी है और राजस्व में इसकी हिस्सेदारी पिछले साल के 20 प्रतिशत की तुलना में कम होकर महज आठ प्रतिशत रह गयी है। वितीय क्षेत्र में भी सुस्ती रही है।सर्वेक्षण के अनुसार, पीआर खर्च में निजी क्षेत्र अभी भी 95 प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है।

नवरात्रि पर विशेष»

प्रकृति है, सृष्टि है, सर्वशक्ति है मां

देवी शक्ति का स्वरूप हैं। यह शक्ति तन, मन और क्रिया की शक्तियों का प्रतीक है। स्वास्थ्य, मन की दृढ़ता व कर्म की निरंतरता ही शक्ति के केंद्र में हैं। यही जीवन भी हैं और यही देवी भक्ति का सार भी। देवी महिमा पर सूर्यकांत द्विवेदी का आलेख

मां शब्द मात्र नहीं, पूरा संसार है। इससे बढ़ कर कोई शब्द नहीं। कोई पूजा नहीं। मां है क्या? जन्म देने वाली, पालने वाली, बच्चे को आगे बढ़ाने वाली या इससे अधिक कुछ और। निस्संदेह, मां के आगे सभी परिभाषाएं और शब्दकोश शून्य हैं। देवी शास्त्र में मां की उत्पत्ति के तीन कारक बताए गए हैं। पहला है इच्छा, दूसरा है शक्ति और तीसरा है क्रिया। मां से अलग होकर कोई भी किसी भी प्राणी में ये तीनों चीजें शामिल नहीं कर सकता। इच्छा, शक्ति और क्रिया का नाम ही जीवन है। यही दुर्गा पूजा है। यही श्री दुर्गा सप्तशती का सार।

रणक्षेत्र में भवानी असुरों से युद्ध कर रही हैं। देवी के अनेकानेक रूप भी असुरों का वध कर रहे हैं। जहां देखो, वहां देवी। जहां देखो, वहां परमेश्वरी। असुर परेशान। असुर बोले- तुम तो अन्य देवियों के साथ युद्ध कर रही हो। अकेले युद्ध करोगी तो तुम में यह साहस नहीं होगा। देवी ने कहा कि यह सब मेरे ही रूप हैं। मैं अकेली हूं। जिस प्रकार तुमको ये देवियां अनेकानेक रूप में दिखाई दे रही हैं, तुम इनको मेरे में ही समाहित होते देखोगे। देवी भगवती ने समस्त शक्तियां अपने में समेट लीं। वह अब दुर्गा थीं। दुर्गम स्थिति को जो पार लगा दे, वही दुर्गा है। महिषासुर, चंड-मुंड, शुंभ-निशुम्भ और मधु-कैटभ के साथ रण में देवी भगवती ने संघीय शक्ति का ही संदेश दिया है।

शक्ति है क्या? राम से देवी का क्या नाता है? चैत्र हों या शारदीय नवरात्रि, देवी भगवती राम के साथ ही क्यों आती हैं। चैत्र में रामनवमी होती है। शारदीय नवरात्रि में विजय दशमी। भारतीय संस्कृति में राम मर्यादित संस्कारों और संस्कृति के प्रतीक हैं। राम और सीता आदर्श पति-पत्नी हैं और दोनों मर्यादा, श्रद्धा, विश्वास के प्रतीक। उन्होंने पारिवारिक संस्कारों और राज व्यवस्था में जो संस्कार दिए, वही संस्कार हमारी पूंजी हैं। राम से बढ़कर मर्यादा की उपमा दी ही नहीं जा सकती। राम ने समाज को एक किया। छोटी-छोटी जातियों को एकत्र करके एक सेना बनाई। महापराक्रमी रावण इसी शक्ति के आगे हार गया और अहंकार चूर हो गया।

भगवती ने भी असुरासुर संग्राम में यही किया। देवी कोई मूर्ति नहीं हैं। देवी कोई स्त्री नहीं हैं। देवी कोई काल्पनिक चरित्र नहीं हैं। देवी तो शक्ति हैं। यह शक्ति तो हर ईसान, हर जीव-जंतु में होती है। कोई पहचान लेता है। कोई नहीं पहचानता। हनुमान जी को भी कहां पता था कि वह समुद्र पार कर सकते हैं। उनको शक्ति का अनुभव कराया गया तो विवेक जाग गया। वे लंका पहुंच गए। लंका जला डाली।

राशि के अनुसार देवी पाठ

मेष- दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय नौ दिन तक पढ़ें। **वृषभ**- दूसरा अध्याय, **मिथुन**- सातवां अध्याय, **कर्क**- तीसरा अध्याय, **सिंह**- तीसरा अध्याय, **कन्या**- दसवां अध्याय, **तुला**- छठा अध्याय, **वृश्चिक**- आठवां अध्याय, **धनु**- ग्यारहवां अध्याय, **मकर**- आठवां अध्याय, **कुंभ**- चौथा अध्याय और **मीन**- नौवां अध्याय

शक्ति को हम कई रूपों में देखते हैं। हम नारी शक्ति के रूप में उसको देखते हैं, हम उसको ऊर्जा के रूप में पाते हैं, हम उसको आत्मबल के रूप में देखते हैं, हम उसको माया-मोह के रूप में देखते हैं। हम एक ही देवी को विद्या, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, विज्ञान, युद्ध कौशल आदि रूपों में देखते हैं। देवी भगवती के शब्दों में - मैं हर प्राणी में मूर्त व अमूर्त रूप में हूं। अजन्मा हूं। अपरिमित हूं। अपरा हूं। अपराजिता हूं। सर्वमंगला हूं। सर्वशक्ति हूं। प्रकृति हूं। सृष्टि हूं। समष्टि हूं। अर्थात मां हूं।

देवी रहस्य : श्री दुर्गा सप्तशती का प्रारम्भ देवी कवच से है। यह देवी कवच क्यों है? देवी को समस्त देवताओं ने अपनी-अपनी शक्ति और अस्त्र-शस्त्र प्रदान किए। समस्त शक्तियों को प्राप्त करने के बाद देवी एकाकार हुईं। वह दुर्गा बन गईं। आज भी हम बलवान और दिलेर स्त्री की तुलना दुर्गा से ही करते हैं। वाणी में मिठास हो तो कहते हैं वाणी पर साक्षात सरस्वती विराजमान हैं। युद्ध विजय को हम अपराजिता की संज्ञा देते हैं। कवच में समस्त दिशाओं, समस्त ग्रह-नक्षत्र, भूत-प्रेत, पिशाच, गंधर्व, राक्षस से देवी सुरक्षित करती हैं। मां भी तो यही चाहती है, उसकी संतान सर्वत्र सुखी रहे। इसलिए, देवी कवच में शरीर के समस्त अवयवों की शक्ति का आख्यान है। अर्थात स्वास्थ्य को प्रथम माना गया है।

शक्ति और शक्ति के संदेश

दुर्गा जी के तीन ही स्वरूप हैं। ये तीनों ही स्वरूप महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती हमारे जीवन के अलग-अलग बल यानी शक्ति को रेखांकित करते हैं। अर्थात आत्मबल (तन, मन, प्रकृति, संतति), जनबल (विद्या, बुद्धि, विवेक, कला, संस्कृति, रण) और धनबल (धन, धान्य, सुख, शांति और समृद्धि)। सभी कुछ इसी पर केंद्रित है। एक बार किसी ने प्रश्न किया कि समस्त प्रसिद्ध देवी स्थान पर्वतों पर ही क्यों हैं? उत्तर यही है- आत्मबल और शारीरिक बल की परीक्षा हेतु। देवी ने प्रकृति से परिवार और परिवार से राष्ट्र तक एकसूत्रीय एकता का संदेश दिया है। वह तन, मन, जन और रण सभी में शक्ति का अनुभव करने, अभय रहने और नित-नई शक्ति का संचार करने का संदेश देती हैं। तन-मन स्वस्थ नहीं तो सब निरर्थक। इसलिए समस्त ग्रह और नक्षत्र उनके अधीन हैं। वह सिंह पर सवार हैं। सिंह शक्ति का द्योतक है। आत्मबल का प्रतीक।

शक्ति पूजा के तीन संदेश

शक्ति और श्री दुर्गा सप्तशती तीन चीजों पर केंद्रित है- इच्छा (प्रथमचरित्र), शक्ति (मध्यम चरित्र) और क्रिया (उत्तर चरित्र)। इच्छाओं को नियंत्रित करें। शक्ति का अनुभव करें। क्रिया करें यानी कर्म करें।

देवी महिमा »

सब कुछ समाहित है भगवती में

ऐसे तो महामाया की आराधना के कितने ही आधार तत्व वेद-पुराण, स्मृति व उपनिषद् आदि ग्रंथों में हैं, लेकिन इन सब में श्री दुर्गा सप्तशती का विशेष मान है। इसे मातृ आराधना का का सेतु कहा गया है। दुर्गा सप्तशती के द्वितीय अध्याय से मातृ महिमा का विशद् वर्णन है और ज्ञात होता है कि कोटि-कोटि देवताओं के दिव्यांश से मातृ देवी की उत्पत्ति हुई है। यही कारण है कि शक्ति, बल, शौर्य व महिमा में मां का नाम सबसे ऊपर है। देवी जी का मुख शिवशंकर के तेज से, सिर में बाल यमराज के तेज से, भुजाएं श्री विष्णु के तेज से, दोनों चरण ब्रह्मा के तेज से और अंगुलियां सूर्य के तेज से प्रकट हुईं। हाथों की अंगुलियां वसुओं के तेज से, नासिका कुबेर के तेज से, दंत प्रजापति के तेज से, तीनों नेत्र अग्नि के तेज से, भवें संध्या के तेज से और कान वायु के तेज से प्रकट हुए।

शरीर के बाद वस्त्र-आभूषण और शृंगार की चर्चा आई है। भगवान शिव से शूल, विष्णु से चक्र, वरुण से शंख, अग्नि से शक्ति, वायु से धनुष व वाण भरे दो तरकश, इंद्र से वज्र और घंटा, यमराज से दंड, वरुण से पाश, प्रजापति से स्फटिकाक्ष की माला और ब्रह्मा जी से कमंडल प्राप्त हुआ। सूर्यदेव ने उनके रोमकूपों में किरणों का तेज भर दिया तो काल देवता ने उन्हें चमकती हुई ढाल व तलवार प्रदान की। क्षीरसमुद्र ने हार और सदैव नवीन रहने वाले द्वय वस्त्र प्रदान किए, कुंडल, कड़ा, नुपूर, हंसली व अंगूठियों से उन्हें शृंगारित किया। विश्वकर्मा ने निर्मल फरसा, अस्त्र व अभेद्य कवच तो जलधि ने सुंदर फूलों की मालाएं दीं। कुबेर ने मधु से भरा पात्र तो शेषनाग ने नागहार प्रदान किया। इस प्रकार मां दुर्गा सभी देवी-देवताओं के अंश से उत्पन्न और शृंगारित हैं। तभी तो वे सभी देवगणों में सर्वाधिक बलशाली हैं।

देवी पुराण में अंकित है कि एकमेव देवी की आराधना से सभी देवता प्रसन्न होते हैं। सचमुच देवी परम कल्याणकारी व महाशक्ति स्वामिनी हैं, जिनकी कृपा से हरेक कार्य सहज व रूरल रूप से सम्पन्न हो जाता है।

आस्था स्थली: घटजई देवी का मंदिर, पंचगनी, महाराष्ट्र

यहां शिवाजी ने की थी देवी पूजा

देश के हर हिस्से के अपने लोक देवता होते हैं। आप देश के जिस कोने में भी जाएंगे, आपको कुछ ऐसे मंदिर मिल जाएंगे, जो स्थानीय मान्यताओं और परंपरा से आबद्ध होते हैं। पहाड़ों की खूबसूरत वादियों के बीच पंचगनी में भी एक ऐसा ही मंदिर है। पंचगनी में घटजई देवी के मंदिर को लोग पहाड़ों की देवी कहते हैं। छोटा-सा ये मंदिर आसपास के लोगों के बीच आस्था का बड़ा केंद्र है। जैसे उत्तराखंड में धारी देवी का मंदिर है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वह पहाड़ों की रक्षा करती हैं, उसी तरह घाटों की रक्षा करने वाली हैं घटजई देवी।

देश के अलग-अलग हिस्सों में शक्ति की देवी के मंदिर जरूर हैं, पर वे स्थानीय नामों से जाने जाते हैं। घटजई देवी का मंदिर कितना पुराना है, इसके बारे में सही-सही नहीं पता चलता है। पर कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना छत्रपति शिवाजी ने की थी। इस आधार पर मंदिर लगभग 450 साल पुराना है। हालांकि जनश्रुतियों के मुताबिक मां का यह मंदिर और भी पुराना है। स्थानीय लोग इसे हजारों साल पुराना मानते हैं। वास्तव में घटजई मां भवानी का ही एक रूप हैं।

मंदिर के गर्भ गृह में दो मूर्तियां हैं। एक मूर्ति मां घटजई देवी की है तो दूसरी पंचगनी गांव की कुलदेवी कालेश्वरी की प्रतिमा है। दोनों को मंदिर में एक साथ स्थापित किया गया है। दोनों ही मूर्तियां सुनहरे रंग की हैं। दर्शन से प्रतीत होता है, मानो देवी ममता से भरी भक्तों को आशीर्वाद दे रही हैं। मंदिर के परिसर मे दीप स्तंभ स्थापित किया गया है, जिस पर आने वाले श्रद्धालु आस्था का दीप जलाते हैं।

मंदिर का परिसर अत्यंत साफ-सुथरा है। खूब हरियाली है। भक्तों के आराम करने और साफ-सफाई की अच्छी व्यवस्था है। वैसे तो मंदिर में लोग सालों भर पूजा करने पहुंचते हैं, पर होली के बाद चैत्र महीने में यहां बहुत बड़ा मेला लगता है। यह मेला पंचगनी का बड़ा मेला होता है। इस मेले में स्थानीय लोग बड़ी संख्या में शिरकत करते हैं।

कैसे पहुंचें : घटजई देवी का मंदिर पंचगनी शहर में टेबल लैंड के पास ही है। पंचगनी के मुख्य बस स्टैंड से पैदल चल कर भी आप मंदिर तक पहुंच सकते हैं। वैसे अच्छा होगा कि पंचगनी घूमने के लिए एक टैक्सी बुक करें, टैक्सी वाला आपको घटजई देवी के मंदिर भी लेकर जाएगा।

जानें भारत में कब से मिलेगी

टाटा ने पेश किया टियागो का इलेक्ट्रिक वैरियंट

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

टाटा मोटर्स की ब्रिटेन की सब्सिडेयरी टाटा मोटर्स यूरोपियन टेक्निकल सेंटर (टीएमईटीसी) ने जुलाई में संकेत दिए थे कि वह इलेक्ट्रिक विहिकल लॉन्च करेगा। इसके बारे में ट्वीट कर जानकारी दी गई थी और अब मिलब्रूक में हुए एक इवेंट में टाटा ने इलेक्ट्रिक वैरियंट को पेश कर दिया। इस छोटी कार को इसके अलावा टाटा ने इंडिका विस्टा और बोल्ट का भी इलेक्ट्रिक वर्जन तैयार किया है। ये सभी कारें एलसीवी इवेंट में पेश की गईं। कंपनी का दावा है कि Tiago EV कार स्पॉर्ट मोड में 11 सेकंड के भीतर 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेती है। इसकी अधिकतम रफ्तार 135 किमी प्रति घंटा है। टाटा टियागो के इस इलेक्ट्रिक वैरियंट में 85 किलोवाट का मोटर लगा है, जो कि 200 न्यूटन मीटर का अधिकतम टॉर्क जेनरेट करता है। इस इलेक्ट्रिक वीइकल में फ्रंट वील ड्राइव दिया गया है। बता दें कि इलेक्ट्रिक वाहनों में सिंगल स्पीड गियरबॉक्स होता है। कंपनी का दावा है कि टाटा टियागो का यह नया वर्जन पूरी तरह से चार्ज होने पर 100 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। कार प्रॉडक्शन स्टेज के काफी करीब पहुंच चुकी है और इसे जल्द ही भारत में भी लॉन्च किया जा सकता है। यह पहली बार नहीं है जब टाटा ने इलेक्ट्रिक वैरियंट पेश किया है। इससे पहले बोल्ट का भी इलेक्ट्रिक वैरियंट पेश किया जा चुका है। इसी तकनीक को कंपनी टियागो में भी इस्तेमाल कर सकती है। टियागो में कम कीमत वाल प्लैटफॉर्म इस्तेमाल किया गया है। टाटा नैनो का भी इलेक्ट्रिक वैरियंट ला सकती है। भारत में टाटा टियागो का इलेक्ट्रिक वैरियंट अगले साल के अंत तक आ सकता है। टाटा टियागो को भारत में 2016 में लॉन्च किया गया था और यह खूब पॉप्युलर हुई थी। इसका बेस मॉडल 3.28 लाख रुपए और टॉप एंड मॉडल 5.8 लाख रुपए का है।

चीन की चेरी इंटरनेशनल की नजर भारतीय कार बाजार पर

मुंबई। एजेंसी

चीन की टॉप कार एक्सपोर्टर चेरी इंटरनेशनल भारतीय बाजार में कदम रखने की संभावना खंगाल रही है। चेरी का अपने देश में टाटा मोटर्स की जगुआर लैंड रोवर यूनिट के साथ ज्वाइंट वेंचर है। चेरी के चेयरमैन ने कहा कि कंपनी इंडिया में आने के लिए इस पार्टनरशिप का सहारा ले सकती है या दूसरे विकल्पों पर गौर कर सकती है।

चेरी के चेयरमैन विन तोंग्याओ ने पिछले सप्ताह फ्रैंकफर्त मोटर शो के दौरान ईटी से कहा था, 'इंडिया शानदार विरासत वाला महान देश है। टाटा ग्रुप के साथ हमारी पार्टनरशिप है। हम इंडिया में कदम रखने के लिए एक टाई-अप पर विचार कर सकते हैं।' उन्होंने कहा था, 'यह गठजोड़ टाटा मोटर्स के साथ या उसके बिना भी हो सकता है। अभी कुछ तय नहीं है।' चाइनीज ऑटोमेकर्स भारत में आने के बारे में लंबे समय से बातें कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने यहां अभी कोई प्रॉडक्ट लॉन्च नहीं किया है। हालांकि हाल के समय में उनमें से कुछ ने ठोस कदम उठाए हैं क्योंकि घरेलू बाजार में सेल्स ग्रोथ में सुस्ती के कारण वे नए मार्केट्स की तलाश में हैं। शंघाई ऑटोमोटिव और बेकी फोटॉन ने इंडिया के बारे में योजनाओं पर काम तेज किया है, वहीं चांगन और ग्रेट वॉल ने यहां की अथॉरिटीज के साथ कई बार चर्चा की है। चीन की सरकारी कंपनी चेरी की शुरुआत दो दशक पहले हुई थी। उसने अब तक 60 लाख से ज्यादा गाड़ियां बेची हैं। टाटा मोटर्स ने प्लेटफॉर्म्स और इंजंस के मामले में कोलैबरेशन के लिए चेरी से बातचीत की थी। वह बातचीत चेरी के इंडिया आने की योजनाओं पर भी केंद्रित थी। चीन के अखबार नान्फांग डेली ने 2014 में रिपोर्ट दी थी कि चेरी अपनी क्यूक्यू, ए1 और एम1 माइक्रो सेडांस और ए3 कॉम्पैक्ट कार के प्लेटफॉर्म्स टाटा मोटर्स को बेचने के लिए बातचीत कर रही है ताकि पैसा जुटाकर कर्ज घटाया जा सके। हालांकि संभावित साझेदारी के लिए टाटा मोटर्स के जर्मनी की फोक्सवैगन और फ्रांस की पीएसए ग्रुप के साथ बातचीत शुरू करने के बाद चीनी कंपनी से जुड़ी योजनाएं छोड़ दी गई थीं। हालांकि यूरोपियन ऑटोमेकर्स के साथ बातचीत भी कुछ खास आगे नहीं बढ़ी है।

महिंद्रा लाई देश का पहला ड्राइवरलेस ट्रैक्टर

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

टैबलेट से होगा कंट्रोल, भांप लेगा अवरोध

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने देश का पहला ड्राइवरलेस ट्रैक्टर पेश किया है। इस ट्रैक्टर को टैबलेट के जरिए कंट्रोल किया जा सकेगा। यह अपने आगे आने वाले अवरोधों का पता लगाने में भी सक्षम होगा।इस ट्रैक्टर को चेन्नई स्थित महिंद्रा रिचर्स वैली में विकसित किया गया है। इस ट्रैक्टर को ना सिर्फ भारत में बल्कि यूएसए और जापान जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी उतारा जाएगा। कंपनी की योजना इस तकनीक का इस्तेमाल 20 एच से लेकर 100 एच तक की रेंज वाले ट्रैक्टर्स में करने की है। इस ड्राइवरलेस ट्रैक्टर में नई तकनीक के साथ कई यूनीक फीचर्स का इस्तेमाल किया गया है। ट्रैक्टर में autosteer फीचर दिया गया है जो जीपीएस आधारित तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ट्रैक्टर को सीधी

लाइन में चलाता है। इसमें auto-headland टर्न फीचर दिया गया है जो खेत में जुताई करते हुए सही समय पर ट्रैक्टर को मोड़ देता है, इसके लिए ड्राइवर की जरूरत नहीं। ट्रैक्टर के auto-implemen लिफ्ट फीचर का इस्तेमाल भी खासकर जुताई के समय होगा। यह पीछे लगे टूल को लाइन खत्म होने पर ऊपर उठा लेता है और अगली लाइन की शुरुआत में फिर नीचे कर देता है।महिंद्रा एंड महिंद्रा के फार्म उपकरण क्षेत्र के प्रेसिडेंट राजेश जेजुरिकर ने कहा, 'आज खेती के लिए मशीन की जरूरत और बढ़ गई है क्योंकि मजदूरों की कमी आ गई और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है। ड्राइवरलेस ट्रैक्टर में पिछले साल लॉन्च की गई 'DiGiSENSE' तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इससे हमारे देश के किसानों को काफी फायदा होगा।

विश्व बैंक को GST पर भरोसा, कहा- 8 प्रतिशत से ज्यादा विकास दर की राह पर भारत

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

जीएसटी को लेकर देश में भले ही अलग-अलग सोच बन रही हो लेकिन विश्व बैंक इससे काफी खुश नजर आ रहा है। उसका कहना है कि जीएसटी के चलते भारत की विकास दर 8 प्रतिशत के रास्त पर जा रही है।

खबरों के अनुसार विश्व बैंक इंडिया के प्रमुख जुनैद अहमद ने वस्तु एवं सेवा कर कानून (जीएसटी) को एक संरचनात्मक सुधार करार दिया है। साथ ही उनका कहना है कि इसने भारत के लिए 8 फीसद की ग्रोथ की संभावना को तेज कर दिया है। भारत ने साल 2016-17 के दौरान 7.1 फीसद की रिकॉर्ड ग्रोथ हासिल की थी और चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान यह 5.7 फीसद रही।

एक इंडस्ट्री इवेंट के दौरान भारत में वर्ल्ड बैंक के कंट्री हैड जुनैद अहमद ने बताया,'आज भारत 8 फीसद से अधिक विकास दर से बढ़ने की संभावना की कगार पर है। क्यों? क्योंकि भारत ने अपने बाजार के एकीकृत करने के लिए साहसिक कदम उठाया है। इसलिए जीएसटी में शिफ्ट करना एक संरचनात्मक सुधार है।'

उद्योग मंडल पीएचडी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के सदस्यों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर जीएसटी सही तरीके से क्रियान्वित होता है, वृद्धि को काफी गति मिलेगी। जुनैद अहमद ने कहा, 'एक बाजार के रूप में जीएसटी जो दे सकता है, उसके लिए आपको (भारत) ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए।'

गौरतलब है कि जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में लागू कर दिया गया था। जीएसटी काउंसिल अब तक कुल 21 बैठकें कर चुकी है और काउंसिल की 22वीं बैठक 6 अक्टूबर को होनी है। हालांकि यह पहले से तय समय से 18 दिन पहले हो रही है, पहले यह बैठक 24 अक्टूबर को तय थी।

सुस्ती के दौर से गुजर रही है अर्थव्यवस्था सरकार को बढ़ाना होगा खर्च : SBI रिसर्च

नई दिल्ली। एजेंसी

भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है और वह सुस्ती के दौर से गुजर रही है। एसबीआई रिसर्च ने मंगलवार को जारी किए नोट में यह बात कही है। नोट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले साल सितंबर से ही सुस्ती की तरफ बढ़ रही है। एजेंसी ने स्थिति सुधारने के लिए सार्वजनिक खर्च बढ़ाने का सुझाव दिया है।

एसबीआई रिसर्च की यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है, जब अमित शाह ने जीडीपी के आंकड़ों में आई कमी के लिए तकनीकी वजहों को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि उन्होंने इन वजहों पर विस्तार से कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। ऐसे समय में इस नोट ने साफ कर दिया है कि अर्थव्यवस्था की यह स्थिति तकनीकी वजहों से तो कतई नहीं है।

पिछले साल से ही सुस्ती के दौर में है इकोनॉमी

रिपोर्ट में कहा गया है, ''हमें ऐसा लगता है कि अर्थव्यवस्था पिछले साल सितंबर महीने से ही सुस्ती के दौर में है। यह सुस्ती तकनीकी तौर पर न लघु अवधि के लिए है और न ही ये क्षणिक है।'' रिपोर्ट में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था की इस स्थिति ने सुस्ती को लेकर बहस तो शुरू कर दी है कि लेकिन बहस इसको लेकर हो रही है कि यह मंदी क्षणिक रहेगी या लंबे समय तक।

घटी है जीडीपी की विकास दर

जीडीपी की विकास दर लगातार छठवें क्वार्टर में घटी है और यह तीन साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंची है। जून क्वार्टर में जीडीपी 5.7 फीसदी पर थी। अमित शाह ने इसके लिए तकनीकी वजहों को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने दावा किया था कि विकास दर वित्त वर्ष 2014 में एनडीए की सरकार आने के बाद 7.1 फीसदी पर पहुंची थी।

सरकार को दी खर्च बढ़ाने की हिदायत

एसबीआई रिसर्च ने सरकार को हिदायत दी है कि अर्थव्यवस्था को बेहतर स्थिति में लाने के लिए खर्च बढ़ाया जाना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था को वित्तीय सहारे की जरूरत है, ताकि विकास दर बेहतर स्थिति में आ सके।

आयकर विभाग ने शुरू किया विशेष पोर्टल

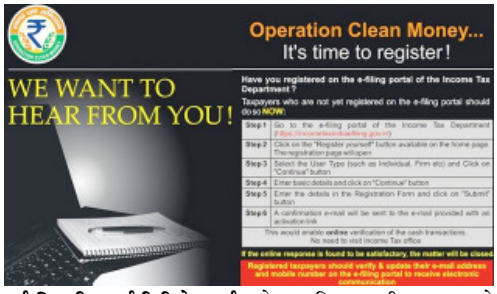

नोटिस आ जाए तो आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

आयकरदाताओं को एक विशेष सुविधा देने जा रहा है। अगर इनकम टैक्स की तरफ से आपको कोई नोटिस आ जाए तो आपको इनकम टैक्स ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक पहली अक्टूबर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक खास ऑनलाइन सिस्टम शुरू कर रहा है। इस ऑनलाइन सिस्टम के तहत इनकम टैक्स बिजनेस मॉड्यूल लॉन्च होगा। विशेष ऑनलाइन पोर्टल लांच किया जाएगा। इसके जरिए स्क्रूटनी से जुड़े सवाल-जवाब ऑनलाइन दिए जा सकेंगे। सवालों के जवाब के लिए आईटी ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। आयकरदाता ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जमा कर सकेंगे। समन, नोटिस, ऑडिट की जानकारी ऑनलाइन मिलेगी। इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह सुविधा दिल्ली, मुंबई समेत देश के 100 शहरों के टैक्स पेयर्स के लिए शुरू की जाएगी।

विशेष पोर्टल से होगी सुविधा

मौजूदा समय में कुछ चुनिंदा शहरों में ही ई-मेल के जरिए नोटिस का मिलता है, उसी ई-मेल के जरिए जवाब दिया जा सकता है। इसके लिए विशेष पोर्टल नहीं है। टैक्स एक्सपर्ट सुशील अग्रवाल का कहना है कि फिलहाल इनकम टैक्स नोटिस का ऑनलाइन जवाब कुछ बड़े शहरों तक तक सीमित है। अगर इनकम टैक्स विभाग इसके लिए कोई विशेष पोर्टल बना रहा है तो यह स्वागत योग्य कदम है। मौजूदा समय में अगर कोई नोटिस ऑनलाइन भी किसी को भेजी जाती है तो उसी ई-मेल में उसको जवाब देना होता है। ऐसे में इस बात की गारंटी नहीं है कि वह मेल द्वारा भेजा गया जवाब उस अफसर तक पहुंचा या नहीं, जिस अफसर ने वह मेल भेजा था। अब विशेष पोर्टल बन जाने के बाद इस बात की गारंटी होगी कि आपने नोटिस के जवाब में जो जवाब या दस्तावेज भेजा है, वह इनकम टैक्स विभाग को मिल गया है।

कैसे भेजेंगे जवाब

विशेष पोर्टल में आयकरदाता अपने पैन नंबर डालकर अपनी आईडी बना सकता है। आईडी बनते ही उसका पासवर्ड आपके मैसेज कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर आपको कोई इनकम टैक्स नोटिस मिलेगा तो आप उसी आईडी के जरिए उस नोटिस का जवाब दे सकेंगे। इसके अलावा एक अहम बात यह है कि आप उस आईडी को खोलकर यह भी देख सकेंगे कि आपने जो नोटिस भेजा है, उसकी स्टेट्स क्या है। इसके लिए आपके आईडी पर इनकम टैक्स विभाग सभी तरह की जानकारियां भी देगा। आप घर बैठे इनकम टैक्स विभाग के सारे सवालों के जवाब दे सकेंगे।

अब इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा आसान

हर जिले में तैनात किए जाएंगे TRP

नई दिल्ली। एजेंसी

देश के हर जिले में जल्द ही छोटे करदाताओं को आयकर रिटर्न भरने में मदद के लिये कम से कम एक प्रशिक्षित व्यक्ति होगा। आयकर विभाग ने 7,600 अतिरिक्त विशेषज्ञों की नियुक्ति का प्रस्ताव किया है। इन विशेषज्ञों की सेवाएं मोबाइल एप पर भी उपलब्ध होंगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 2006 की 'टैक्स रिटर्न प्रीपेयरर'(टीआरपी) योजना को डिजिटल रूप देने और देश के सभी 708 जिलों को शामिल करने का फैसला किया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के मुकाबले टीआरपी कुछ राशि लेकर कर रिटर्न भरने में करदाताओं की मदद करते हैं।

आयकर विभाग की रूपरेखा के अनुसार, 'प्रत्येक जिले में पर्याप्त संख्या में टीआरपी नियुक्त करने का प्रस्ताव है। इसके लिये टीआरपी की संख्या मौजूदा 5,400 से बढ़ाकर 13,000 की जाएगी।' इसके अनुसार, 'प्रस्ताव के तहत देश के प्रत्येक जिले में कम से कम तीन टीआरपी होने चाहिए'। परियोजना पर काम कर रहे एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इसका मकसद चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास गये बिना करदाताओं को कर रिटर्न फाइल करने को सुगम बनाना है।

विभाग के अधिकारी ने कहा, 'आईटीआर रिटर्न भरना अब भी कई लोगों के लिये आसान कार्य नहीं हैं। टीआरपी योजना एक दशक पहले शुरू की गयी थी, इसके पीछे मकसद यह है कि करदाताओं को कर भरने को लेकर कम लागत पर सेवा मिले।' उन्होंने कहा, 'फिलहाल देश के हर जिले में टीआरपी नहीं है। कर आधार बढ़ने के साथ सरकार का करदाता सेवा बढ़ाने के निर्देश के बाद नई योजना तैयार की जा रही है। अधिकारी ने कहा, '7,600 नये टीआरपी को प्रशिक्षण दिया जाएगा और आयकर विभाग उनकी नियुक्ति करेगा। अधिकारी के मुताबिक नई डिजिटल योजना के तहत करदाता जल्दी शुरू होने वाला मोबाइल एप 'आयकर मित्र' पर लॉग इन कर करीब में काम करने वाले टीआरपी की जानकारी ले सकेंगे। यह एप उसी प्रकार का होगा जैसा कि ऑनलाइन टैक्सी सेवा प्रदाता उबर और ओला जैसी कंपनियां यात्रियों के लिये उपलब्ध कराते हैं।

आर्थिक अपराधियों की संपत्ति जब्त करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी

नई दिल्ली। एजेंसी

कानून मंत्रालय ने एक नए प्रावधान के साथ देश छोड़कर भागने वाले आर्थिक अपराधी और डिफॉल्टर्स की संपत्ति जब्त करने का अधिकार देने वाले विधेयक के मसौदे पर सहमति दे दी है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। मंत्रालय विधेयक को संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश करने से पहले उसमें एक विशेष छूट वाला प्रावधान (सेविंग क्लॉउज) शामिल करना चाहता था।

यह प्रावधान जिसे सेविंग क्लॉज कहा गया है, कानून में कुछ छूट उपलब्ध कराता है। प्रस्तावित कानून वैसे मामलों में लागू होगा जहां अपराध 100 करोड़ रुपये से अधिक के हो। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2017-18 के बजट भाषण में ऐसे भगोड़ों की संपत्ति जब्त करने को लेकर कानून में बदलाव या नया कानून लाने का वादा किया था। यह आर्थिक अपराध करने वालों को देश छोड़कर भारतीय कानून की प्रक्रिया से बचने वाले आर्थिक अपराधियों पर अंकुश लगाने पर जोर देता है। विधेयक

वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) को आर्थिक अपराधी को भगोड़ा घोषित करने और संपत्ति जब्त करने को लेकर आवेदन देने की अनुमति देता है। एफआईयू वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाली तकनीकी खुफिया इकाई है। मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून के तहत अदालत को मामले की सुनवाई की जिम्मेदारी दी जाएगी।

वित्त मंत्रालय ने विधेयक पर कैबिनेट नोट का मसौदा तैयार किया था और उस पर कानून मंत्रालय की राय मांगी थी। सूत्रों ने कहा कि मंत्रालय ने विधेयक के प्रावधानों से सहमति जताते हुए इसमें विशेष छूट का प्रावधान शामिल करने का सुझाव दिया है। उसका कहना है कि प्रस्तावित विधेयक के प्रावधानों का मौजूदा कानून के प्रावधानों पर प्रभाव पड़ेगा, अतः उन प्रावधानों का असर बनाए रखने के लिए विधेयक में विशेष छूट वाला प्रावधान शामिल किया जाना चाहिए।

ऐसे मौजूदा कानून जिनके तहत अपराधियों के खिलाफ सुनवाई चल रही है, उसमें प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन अधिनियम कानून, 2002 (सरफेसी), बैंकों के बकाये ऋण की वसूली और वित्तीय संस्थान कानून तथा दिवाला एवं ऋण शोधन संहिता (आईबीसी) शामिल हैं।

ऐसा हुआ तो 80 रुपए से घटकर 40 रुपए लीटर पर आ जाएगा पेट्रोल

नई दिल्ली। एजेंसी

पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों के बीच एक राहत भरी खबर है। अगर ऐसा हुआ तो आज 80 रुपए लीटर में बेचा जा रहा पेट्रोल 40 रुपए लीटर पर आ जाएगा। साथ ही सभी राज्यों में पेट्रोल और डीजल की समान कीमत होगी। खबर यह है कि राज्यों में इस बात पर सहमति बन गई है कि प्राकृतिक गैस पर लगने वाले वैट की अधिकतम सीमा 5 फीसदी कर दी जाए।

ऐसे में यदि पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो इनकी कीमत आधी रह जाएगी। मालूम हो, पेट्रोलियम उत्पादों को अभी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य इस बात पर भी सहमत हो गए हैं कि उद्योग जगत में लगने वाले पेट्रोलियम उत्पादों के दाम कम कर दिए जाएं। हालांकि यह अभी तय नहीं हुआ है।

जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में इस पर फैसला होगा। लेकिन इस बारे में केंद्र और राज्यों के बीच पहले दौर की बातचीत हो चुकी है। अभी गेंद राज्यों के पाले में है। राज्यों का रुख अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि राज्यों को पेट्रोल-डीजल की बिक्री से सबसे ज्यादा कमाई होती है। अगर राज्य पेट्रो उत्पादों को जीएसटी के दायरे में करने पर सहमत हो जाते हैं तो फिर पूरे देश में पेट्रोल-डीजल के रेट न केवल सस्ते हो जाएंगे बल्कि एक समान होने की उम्मीद भी है।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्प्लेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।